

Day-3

Q.

20

1979

Discuss how the Government of India Act, 1935 laid the constitutional foundation of the modern Indian state. Which key features of this Act were later retained in the Indian Constitution? (14)

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने आधुनिक भारतीय राज्य को संवैधानिक नींव कैसे रखी? इसके कौन-से प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए? 38 M



Ranjan Kumar

2:19:08 PM

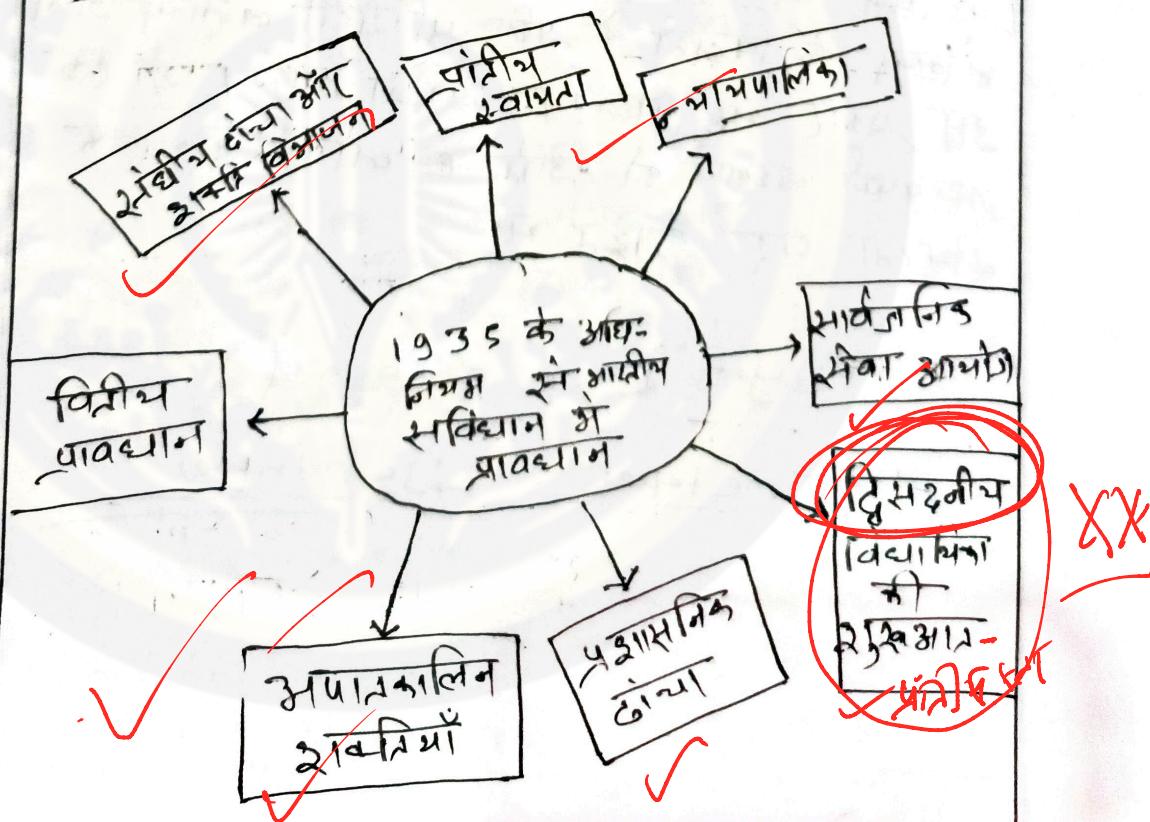
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आवृत्ति भाषीय कोन से संविधान के से रखी? उसके पश्चात प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किये गए।

उत्तर

✓
भारत सरकार अधिनियम 1935, विहित भारत के इतिहास में सबसे भवित्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक था। उस अधिनियम का उद्देश्य भारत में संघीय संरचना और द्विशासन की उत्क्षेपण करना था, जबकि उसीमि नियंत्रण विहित दावों में था। उस अधिनियम ने आवृत्ति भाषीय राज्य की संवेधानिक वीक्षण में भवित्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने संघीय दावे, पांतीय राज्यता, अपातकाल और द्विशासन के कुछ मूलभूत विशेषताओं को बहुत किया था लाद में भारतीय संविधान (1950) के लिए पैरणा रूपों बने।

improves

** 1935 भारत सरकार अधिनियम के विनियिक प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किये गए



संघीय दाचा और उत्तरि विभाजन

- इस अधिनियम ने पहली बार भारत को एक संघीय दाचा में ढाला। इसने केन्द्र और प्रोवीन्स के बीच शाखियों का विभाजन किया जो भारतीय संविधान में केन्द्र सूची, प्राप्ति सूची और समवर्ती सूची के रूप में देखा जाता है। यह संघीय व्यवस्था आज भी भारतीय राजन का मूल ढाचा है।

प्रांतीय स्वायत्ता

- इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्ता दी जिससे उन्हें ऑटोरिक मामलों में विनियोग की ~~उत्तरि~~ मिली। भारतीय संविधान ने भी राज्यों को स्वायत्ता पदान की विस्तृत व अपन संघीय हितों की रक्षा कर सकें।

संघीय न्यायालय

इस अधिनियम के बहुत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में विकसित हुआ है जो सर्वेधारिक व्याप्ति और न्याय का सर्वोच्च नियंत्रण है।

~~भाविति~~ सेवा आयोग

- इस अधिनियम ने ~~भाविति~~ सेवा आयोग की स्थापना की जो सरकारी सेवाकोषों में जर्ती के लिए नियोगदार थे। यह भारतीय संविधान में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में पायी है।

हिंसकीय विधानिका की शुरूआत

इस अधिनियम ने हिंसकीय विधानिका की शुरूआत की (जिसमें संघीय विधानसभा (निम्नलोक संघ) संघीय परिषद (उच्चसंघ) की अहंकारिता भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में परिवर्तित है।

Provisions

प्रशासनिक दाता

- इस अधिनियम ने प्रशासनिक दाता, जैसे गवर्नर की नियुक्ति की जिसे भारतीय संविधान में राष्ट्रपाल की भूमिका के रूप में उन्नीत किया जाता है।

अपारकालिन समिक्षा

इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और गवर्नर के अपारकालिन समिक्षा की जिस संकेत में उपयोग किया जा सकता था। अहं अवधारणा भारतीय संविधान में अनु० 352, 356 और 360 के रूप में मौजूद है।

वित्तीय प्रबंधन

- के बाद और प्रोटो के बीच राजस्व के बहार की व्यवस्था की भारतीय संविधान में वित्तालोग (अनु० 280) के रूप में उपलब्ध गया है।

* निकर्ष

लोक

मार्ट संस्कार अधिनियम 1935 मार्टीय १९३५ की संवैधानिक नीति द्वारा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संघीय कानून, प्रतिनिधित्वात्मक, सार्वजनिक सेवा, अपारकालिन शासिता औले प्रवधानों के आधुनिक भारतीय राज्य की नीति एवं इस द्वारा को इस संघीय लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जो आज भी भारतीय राष्ट्राधारी की रीढ़ है।

Rajya Sabha (Grand)

Second Part
Missing

17/36

1919
Check/Bk/Bk